

इसरो और जाकसा के बीच समझौता-ज्जापन को कैबिनेट की मंजूरी

सन्दर्भ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और जापानी एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जाकसा) के बीच समझौता ज्जापन पर अपनी मुहर लगा दी है। वदिति हो का 11 नवंबर, 2016 को टोक्यो में इस समझौता-ज्जापन पर हस्ताक्षर किये गए थे।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस समझौता-ज्जापन का मुख्य उद्देश्य, अंतरिक्ष अनुसंधान में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना और बाह्य अंतरिक्ष में शांतपूरण गतिविधियों में एक-दूसरे के सहयोग से अभियान चलाना है। दोनों ही देश इन अभियानों और परस्पर सहयोग को अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुए बढ़ावा देंगे।
- यह समझौता-ज्जापन अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारत-जापान के आपसी सहयोग को और आगे ले जाएगा। इसके तहत इसरो और जाकसा पृथ्वी के अवलोकन, उपग्रह संचार और नौवहन, अंतरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान एवं अन्वेषण तथा अंतरिक्ष प्रणालियों व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास में मलिकर कार्य करेंगे।
- इसके मुताबकि, जब तक संयुक्त नविश के लिये लिखित तौर पर कोई सहमति नहीं बन जाती, तब तक इसरो और जाकसा अपनी-अपनी गतिविधियों की लागत का वहन स्वयं करेंगे। गौरतलब है कि इस समझौता-ज्जापन के तहत दोनों एजेंसियों के अभियानों के कार्यान्वयन और अभियान से संबंधित वित्त पोषण की प्रक्रियाएँ संबंधित देश के राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर ही होंगे।

नषिकरष

- भारत और जापान पछिले 5 दशकों से अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में परस्पर सहयोग को आगे बढ़ाने के लिये प्रयासरत हैं। 2003 में जाकसा के गठन के साथ ही "बाह्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में भावी सहयोग के लिये इसरो और जाकसा के बीच अक्टूबर 2005 में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे। इसके बाद दोनों एजेंसियों ने चंद्र अन्वेषण, उपग्रह नौवहन, खगोल विज्ञान के संबंध में सहकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये हैं।
- दरअसल, 05 अप्रैल, 2016 को नई दल्लि में इसरो-जाकसा की द्वपिक्षीय बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक के दौरान वर्ष 2005 में हुए समझौते को आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई थी। तदनुसार, 11 नवंबर, 2016 को टोक्यो में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जाकसा) के बीच बाह्य अंतरिक्ष में उपग्रह दशिा-नरिदेशन और खगोलीय खोज में सहयोग बढ़ाने के लिये समझौता-ज्जापन पर हस्ताक्षर किये गए थे जसि अब कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हो गई है।